हवा से बनी 200 मेगावॉट बिजली खरीदेगी बीएसईएस

नई दिल्लीः 3 अप्रैल, 2018। बीएसईएस डिस्कॉम्स, हवा से बनने वाली 200 मेगावॉट बिजली खरीदेगी। इसे सामान्य बोलचाल में विंड पावर कहा जाता है। बीआरपीएल ने 150 मेगावॉट विंड पावर और बीवाईपीएल ने 50 मेगावॉट विंड पावर के लिए समझौता किया है। यह समझौता 25 वर्षों के लिए है। खास बात यह है कि हवा से बनने वाली यह बिजली काफी सस्ती भी है। सिर्फ 2.52 रूपये प्रति यूनिट की दर से बीएसईएस को यह बिजली मिलेगी।

बीएसईएस ने एसईसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरशन ऑफ इंडिया के साथ हवा से बनी बिजली खरीदने का समझौता किया है। बीएसईएस को यह बिजली अभी से 18 महीने बाद यानी नवंबर 2019 से मिलनी शुरू होगी और अगले 25 वर्षों तक मिलती रहेगी।

इस बिजली खरीद समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से न्यूनतम दरों पर विंड पावर की खरीद संभव हो पाएगी। लंबी अवधि के लिए विंड पावर की थोक–खरीद दर औसतन 4.5 रूपये प्रति यूनिट है, जबकि यहां से यह बिजली सिर्फ 2.52 रूपये प्रति यूनिट की दर पर मिल जाएगी। उपभोक्ताओं के लिए प्रतियोगितात्मक दरों पर बिजली की खरीद के अलावा, इस विंड पावर से बीएसईएस को डीईआरसी द्वारा तय रिन्युएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यानी आरपीओ को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी बीआरपीएल ने पीटीसी के साथ 100 मेगावॉट विंड पावर के लिए समझौता किया था, जो इसी साल नवंबर महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह, ताजा समझौते के बाद, बीएसईएस को आने वाले दिनों में 300 मेगावॉट विंड पावर मिलेगी।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक – दिल्ली में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ बीएसईएस डिस्कॉम्स इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं पर इस का न्यूनतम बोझ पड़े। इसीलिए, बीएसईएस सभी विकल्पों को तलाशकर, काफी कम कीमतों पर अक्षय ऊर्जा की व्यवस्था कर रही है। यह समझौता बीएसईएस द्वारा किए जा रहे ऐसी ही प्रयासों का एक उदाहरण है।

अगर डिस्कॉम्स के पास परंपरागत स्रोतों से मिलने वाली बिजली के साथ–साथ विंड और सोलर पावर भी हो, तो इससे दिल्ली की पीक पावर डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में रोजाना दो बार बिजली की डिमांड उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। गुजरात से आने वाली यह विंड पावर, रात को बिजली की पीक डिमांड को पूरा करने में मदद करेगी।

दरअसल, यह एसईसीआई द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑक्शन है, जिसके तहत गुजरात के कच्छ में पवन ऊर्जा के डेवलपर्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट्स साइन किए जाएंगे। प्रतियोगितात्मक बिडिंग प्रक्रिया द्वारा उनका चयन किया जाएगा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के तौर पर एसईसीआई को चुना गया है। टैरिफ आधारित प्रतियोगितात्मक बिडिंग प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के तहत, यह, ग्रिड से जुड़े विंड पावर प्रोजेक्ट्स से बिजली की खरीद के लिए मध्यस्थ खरीदार के तौर पर कार्य करेगी।

उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 2022 तक कमिशंड सोलर व विंड पावर से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन चार्ज और उत्पादन के नुकसान माफ कर दिए हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

.....